



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1940 (श0)  
(सं0 पटना 511) पटना, बृहस्पतिवार, 31 मई 2018

सं० 11/आ0नी0-I-06/2017 सा0प्र0-7162  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
31 मई 2018

**विषय :-** राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) स्थान आरक्षित करने के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-32 में यह व्यवस्था की गई है कि सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिन्हें सरकार से सहायता मिली हो, में नामांकन में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाय।

तदनुकूल उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप यह निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह आरक्षण संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। आरक्षित कोटि के दिव्यांग उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर नामांकन हेतु चयनित होते हैं, की गणना दिव्यांग के लिए नामांकन के दिये जा रहे 5% आरक्षण के विरुद्ध नहीं की जायेगी, बल्कि उनकी गणना सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में की जायेगी। संविधान में निहित समानता का अधिकार के अनुरूप दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु दिव्यांग किसे कहा जायेगा तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, उससे दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। चयनित दिव्यांग उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के जिस वर्ग से आते हो उसी वर्ग में उनकी गिनती होगी। किसी नामांकन विशेष के लिए चयनित दिव्यांग उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं, तो उनकी गिनती अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायेगी। यदि वे अनुसूचित जनजाति के हैं, तो उनकी गिनती अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायेगी। यदि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं से संबंध

रखते हों, तो उनकी गिनती क्रमशः अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायेगी। इसी प्रकार यदि वे सामान्य वर्ग के हैं, जो उनकी गिनती सामान्य वर्ग के ही विरुद्ध की जायेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र राम,  
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 511-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>